www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 285 | जौनपुर शनिवार, 06 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

मानसून सत्र में फिर आ सकता है महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और उससे जुड़े परिसीमन विधेयक को एक बार फिर पेश किए जाने की संभावना तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के परिणामों के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों ने सरकार का आत्मविश्वास बढ़ाया है। माना जा रहा है कि सरकार अब इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ सकती है।गौरतलब है कि अप्रैल में आयोजित संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया गया था। प्रस्तावित विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान शामिल था। हालांकि संविधान संशोधन से जुड़े इस विधेयक के लिए आवश्यक दो–तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। लोकसभा में हुई वोटिंग के दौरान पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत पड़े थे। कुल 528 सांसदों द्वारा मतदान किए जाने के बावजूद आवश्यक समर्थन का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया था।

टीएमसी में घमासान के बीच ममता के साथ खड़े हुए बाबुल सुप्रियो

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी हलचल के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति अटूट समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह हमेशा ष्दीदीष् के साथ खड़े रहेंगे। गायक से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो ने अपने पोस्ट में उन लोगों पर भी निशाना साधा, जो कभी पार्टी नेतृत्व को खुश करने के लिए हरसंभव कोशिश करते थे, लेकिन अब सत्ता के लालच में पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उन लोगों के विश्वासघात का दर्द झेल रही हैं, जो कभी मंत्री पद पाने के लिए भी सक्रिय रूप से लॉबिंग करते थे।बाबुल ने लिखा, ष्आज चाहे जो भी हालात हों, मैं दीदी के साथ हूं। सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के बावजूद मैं राज्यसभा सांसद के रूप में बंगाल के लिए अपनी क्षमता के अनुसार काम करता रहूंगा।ष् चुनाव कवरेज उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या आयकर विभाग से कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा, ष्मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे किसी जांच एजेंसी का भय नहीं है और मैं ईमानदारी से कर अदा करता हूं।

खेल के रूप में शामिल होने के बाद योग रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न करेगा : पीएम नरेंद्र मोदी

अहमदाबाद, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन चौंपियनशिप–2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग खेल के रूप में शामिल होकर रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर जीवन परंपरा समय के साथ नए चरण में प्रवेश करती है। योगासन की यह विश्व चौंपियनशिप इसी चरण का शुभारंभ है। इस चौंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतियोगी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाएगा। ओलंपिक या कोई भी बहुखेल प्रतियोगिता हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, उतना सुखद परिणाम आ सकता है। अहमदाबाद में होने जा रही पहली विश्व योगासन चौंपियनशिप की भूमिका अहम होगी।ष उन्होंने कहा, ष्खेल के रूप में योगासन का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा खेल अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, इसलिए योगासन का खेल के रूप में विस्तार होगा, वैसे–वैसे इससे जुड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और इवेंट प्रबंधकों के लिए भी यह नए अवसर लेकर आएगा।ष पीएम ने कहा, ष्एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे। यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यह देखकर खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अब अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। ध्यान, प्राणायाम उनकी जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है।ष उन्होंने कहा, ष्21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया के अलग–अलग देशों में योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

ईडी ने की 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की चल–अचल संपत्ति कुर्क

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब और डीएमएफ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में अनवर ढेबर और सेवानिवृत आईएएस अनिल टुटेजा सिंडिकेट की अब तक 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की चल–अचल संपत्तिं कुर्क (अटैच) की गई है। सिंडिकेट पर चार बड़े घोटालों शराब, कोयला, सट्टा और डीएमएफ से करीब 4,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी ने हाल ही में तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए। इन संपत्तियों की कागजी कीमत (डीड वैल्यू) करीब 200 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार मूल्य 1,000 करोड़ से 1,400 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में रायपुर की पॉश श्ढेबर सिटीश की बेनामी संपत्तियां और गोवा का आलीशान होटल वेस्टिन शामिल हैं। ईडी के मुताबिक, गोवा का यह होटल शराब घोटाले की 110 करोड़ रुपये की काली कमाई से खरीदा गया था। सिंडिकेट से जुड़ी तीन सप्लायर कंपनियों,ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक के 51 करोड़ रुपये के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए हैं। इन कंपनियों से जबरन 50–60 प्रतिशत मुनाफा वसूला जाता था। केवल शराब घोटाले से ही 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की गई।

विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया पौधा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आम का पौधा लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी बचेगी, इसलिए हर नागरिक मातृभूमि के प्रति ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने पर्यावरण व प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए 9 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2017 में शासन संभालते ही डबल इंजन सरकार ने वन महोत्सव के अवसर पर 5 करोड़ पौधरोपण कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। उस समय हमारे सामने तमाम चुनौतियां थीं। न नर्सरी थी और न ही इतने बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुभव था, लेकिन वन एवं अन्य विभागों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। सीएम योगी ने कहा कि 9 वर्ष के अंदर प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया गया, जिससे प्रदेश का फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। पीएम मोदी ने प्रकृति व मातृभूमि के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता स्वरूप तीन वर्ष पहले 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में आज पौधरोपण महाभियान प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम के उद्घोष 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का भी जिक्र करते हुए।

कांवड़ यात्रा को सुगम बनाएगी दिल्ली सरकार, तैयारी पर सीएम रेखा गुप्ता की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। इसके लिए 1 जुलाई से पंजीकरण शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। बैठक में कला एवं संस्कृति मंत्री और कांवड़ समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा, समिति के सदस्य विधायक अजय महावर, अनिल वाजपेयी, करतार सिंह तंवर, संजय गोयल और उमंग बजाज सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड, डूसिब और अन्य संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियों की जानकारियां पेश कीं। राजस्व विभाग ने बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि पिछले वर्ष दिल्ली में 308 कांवड़ शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। पिछले वर्ष पहली बार कांवड़ समितियों को अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने और सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था। समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी, अधिकांश समस्याओं का समाधान हुआ और कांवड़ समितियों ने इस पहल की सराहना की। समीक्षा बैठक में कांवड़ समितियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बड़े शिविरों के लिए मौजूदा अनुदान राशि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टेंट और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर अधिक खर्च आता है। कुछ समितियों ने अनुदान बढ़ाने या पहले की तरह सरकार द्वारा सीधे टेंट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

मंत्री रामलिंगा के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे सीएम शिवकुमार

बंगलूरू, (एजेंसी)। कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद पैदा हुआ राजनीतिक विवाद अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे के बाद से ही सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मंत्री प्रियांक खरगे के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ किया है कि पार्टी इस मामले को बातचीत से सुलझा लेगी। कांग्रेस नेतृत्व अब इस पूरे विवाद को शांत करने में जुट गया है ताकि सरकार और संगठन दोनों पर इसका असर न पड़े। दरअसल, हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया गया था। इस दौरान रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, रेड्डी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और वह बंगलूरू विकास विभाग की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विभाग आवंटन को लेकर हुई बैठक में भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद उनके इस्तीफे की खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने रामलिंगा रेड्डी को अपना करीबी दोस्त बताया। शिवकुमार ने कहा, "वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कैबिनेट में हम सबसे करीबी दोस्तों में हैं। हम इस समस्या को सुलझा लेंगे।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेड्डी की नाराजगी विभाग से जुड़ी है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। उनके बयान को सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना जा रहा है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने भी रामलिंगा रेड्डी के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेड्डी पार्टी और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण नेता हैं। प्रियांक खरगे ने भरोसा जताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पूरे मामले का हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में संवाद की परंपरा है और हर मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाता है। खरगे के बयान से यह साफ संकेत मिला कि कांग्रेस नेतृत्व किसी भी कीमत पर विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहता। रामलिंगा रेड्डी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और उनका बंगलूरू की राजनीति में मजबूत प्रभाव माना जाता है।

भारत का नया मॉडल, वायु प्रदूषण को माना बड़ी चुनौती : मंत्री भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति पर काम कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने जंगल बढ़ाने, जैव विविधता बचाने और नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत करने में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा विकास मॉडल अपना रहा है जिसमें आर्थिक तरक्की भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, पर्यावरण ऑडिट और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण जैसे कई कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि इन योजनाओं का मकसद लोगों की जिंदगी आसान बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि साफ हवा, स्वच्छ पानी और प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 के बाद देश में टाइगर रिजर्व, संरक्षित वन क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि अगस्थ्यमलाई, खांगचेंदजोंगा, पन्ना और हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र जैसे कई भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। इससे पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं में भी प्रकृति बचाने को लेकर रुचि बढ़ रही है और लोग वृक्षारोपण अभियानों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

देश के शिक्षाविदों ने योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश विषय पर की परिचर्चा

दिल्ली ब्यूरो चीफ पी अस्थाना

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर वर्चुअल माध्यम (जूम)से देश के बुद्धिजीवियों द्वारा एक भव्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का मुख्य विषय श्योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेशश रहा, जिसमें राज्य के अभूतपूर्व विकास,सुदृढ़ कानून व्यवस्था और महिला कल्याण की योजनाएँ जैसी जन–कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आ रहे सामाजिक बदलावों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की संयोजक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली की प्रो. पूनम कुमारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे चतुर्दिक विकास की बात की। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि किस प्रकार राज्य में सुदृढ़ कानून–व्यवस्था, व्यापक महिला शिक्षा और सुलभ रोजगार के अवसरों ने आधी आबादी का सशक्तिकरण कर उनके जीवन में एक युगांतरकारी सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रपात किया है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन में उत्तर प्रदेश सुदृढ़,सुरक्षित और प्रगतिशील श्नया उत्तर प्रदेशश बन चुका है।आज उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी,उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता एस.एन. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन नीति और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को रेखांकित किया। विशेष वक्ता के रूप में बेंगलुरु से जुड़े टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के इंजीनियर मैनेजर संजीव निश्टल ने राज्य में बुनियादी ढांचे (प्दतिंजतनबजनतम) के तेजी से हो रहे विकास,नए एक्सप्रेस–वे और औद्योगिक कॉरिडोर के द्वारा हो रहे आर्थिक परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए। मुंबई से जुड़े कमर्शियल टेक्निकल कंसल्टिंग एलएलपी के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार अखौरी ने उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेसश्तकनीकी प्रगति और बढ़ते निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था में व्यापक सुधार और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण जघन्य अपराधों में भारी कमी आई है। कुलदीप उपाध्याय, अंजलि और धीरज आदि युवा वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हो रहे परिवर्तनों की चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ परिचर्चा का समापन हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. शिवानी सक्सेना द्वारा किया गया।सार्थक विमर्श के साथ संपन्न हुए वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस परिचर्चा कार्यक्रम में जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू,वाराणसी समेत देश भर के शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों,शोधार्थियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया।

मायावती ने हिमाचल और जम्मू–कश्मीर संगठन की समीक्षा की

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर इकाइयों की समीक्षा बैठक की। बैठक में संगठन की जमीनी मजबूती, जनाधार विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संगठन को गांव–गांव तक मजबूत करने के साथ चुनावी सफलता को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए एकजुट होकर बीएसपी को मजबूत बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को अपने वोट की सुरक्षा को आत्मसम्मान, इज्जत और अधिकारों की सुरक्षा के समान महत्व देने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के बाद बने राजनीतिक हालात की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, ऐसे में बीएसपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने का अवसर है।

संपादकीय

जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी

अमेरिका में बैठे कांग्रेस हितैषी सैम पित्रोदा (सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा) ने सुदूर भारत की उनींदे से चुनाव प्रचार में करंट पैदा कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी विरासत–कर प्रणाली की सराहना करते हुए भारत में इसकी संभावना पर विचार करने को कहा है। इस एक मशविरा ने भाजपा और उसके नेता नरेन्द्र मोदी को कांग्रेस पर हमले के लिए दोनों हाथों में मुद्दा दे दिया है–एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। वे इसे पुरखों की गाढ़ी कमाई से खड़ी की गई संपत्ति–परिसंपत्ति पर श्पंजाय्र मारने की लुटेरी नीयत मान रहे हैं। उसका श्लूट प्लान जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भीय्र जारी रहने वाला है यानी माता–पिता के जीवित रहते कर लेंगे और उनके बाद वारिसों से भी। वे खुल्लमखुल्ला इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस उनकी संपत्ति छीन कर किसी को (मुसलमानों को?) दे देगी। धन–संपदा मनुष्य की एक स्थायी नैसर्गिक कामना है। इसे हथियाने की बात होगी तो लोग–बाग कांग्रेस से बिदकेंगे ही। पित्रोदा के सहसा सीन में आने के दो दिन पहले तक मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संपत्ति के सर्वेक्षण पर समझा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन कर श्ज्यादा बच्चे पैदा करने वालेय्र और श्घुसपैठिएय्र को दे देगी–महिलाओं से उनके मंगलसूत्र तक छीन लेगी। जबकि कांग्रेस का एजेंडा एक दशक में बढ़ी आय–असमानता की वजहों की जांच का है। पर मैनिफेस्टो से मोदी के जबरदस्ती निकाले जिन ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। तब भी मोदी इन हथियारों की मारकता शेष चुनाव तक बने रहने पर आस्त नहीं थे। वे कांग्रेस और उसके गठबंधन के दुष्प्रचार के आगे डिफेंसिव थे। जो कह रहे थे कि श्मोदी अबकी सत्ता में आए तो न आगे चुनाव होगा, न संविधान बचेगा और न आरक्षण रहेगा।य्र लेकिन पित्रोदा की गलत टाइमिंग ने मोदी का समय सही कर दिया। वे फ्रंट पर हैं और विपक्ष बैकफुट पर। हालांकि कांग्रेस ने सैम की राय को निजी बता कर पल्ला झाड़ लिया है। पर नुकसान की भरपाई मुश्किल है। अमेरिका में कुल विरासती संपत्ति के मूल्य का 55 फीसद हिस्सा सरकार ले लेती है। शेष 45 फीसद पर ही भावी पीढ़ी का हक होता है। यह विश्व के दर्जनों देश में लागू है। भारत में राजीव गांधी सरकार ने वित्तमंत्री वीपी सिंह के सुझाव पर इसे अनुत्पादक मानते हुए निरस्त कर दिया था। पर इस गए विचार ने भारतीय चुनाव में एक नया हलचल पैदा कर दिया है।

अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। बढ़ते कृषि उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और प्रमुख मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वष्रा के स्पष्ट संकेत खेती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि वर्ष 2024 में दक्षिण–पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। गौरतलब है कि विभिन्न रिपोटरे में कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांवों में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन फ्रिज, दोपहिया वाहन और टीवी की खरीदारी भी उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत में पिछले एक दशक में शहरी परिवारों के मुकाबले ग्रामीण परिवारों का खर्च तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति और मांग में भारी इजाफा हुआ है। इससे ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में वृद्धि हुई है। यद्यपि अभी आम चुनाव के बाद जून, 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के मूर्त रूप लेने में कोई दो माह बकाया हैं, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से जिन क्षेत्रों के लिए आगामी पांच सालों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाना शुरू की गई है, उनमें कृषि भी प्रमुख है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत को खाद्यान्न का नया वैश्विक कटोरा माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। गेहूं तथा फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर तथा सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर भारत केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च आदि के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां कोविड–19 की आपदा से लेकर अब तक भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया के जरूरतमंद देशों की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं भारत ने दुनिया भर में कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का अवसर भी मुिट्ठयों में ले लिया है। भारत से कृषि निर्यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनाज, गैर–बासमती चावल, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के अलावा फलों एवं सब्जियों के भारत से निर्यात में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कई छोटे देशों के बाजार भी भारत की मुिट्ठयों में आए हैं। इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है। खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां भारत से निर्यात में वृद्धि नहीं हुई हो। अब भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षो में खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 15 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदाथरे की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं–डेयरी क्षेत्र, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, अनाज का प्रसंस्करण, मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता वस्तुएं पैकेटबंद खाद्य और पेय पदार्थ। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि इन प्रमुख पांच क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं को मुिट्ठयों में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे ग्रामीण भारत लाभान्वित हो रहा है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि फरवरी, 2024 में भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण एवं न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) के स्थायी समाधान के लिए जिस तरह प्रभावी पहल की गई। इस कारण इस सम्मेलन में इन मुद्दों पर कई विकसित देश भारत के किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसे में अब भी भारत अपने किसानों के उपयुक्त लाभ के लिए नीतियां बनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक भंडारण की सुविधा से कृषि एवं ग्रामीण विकास के अभियान को आगे बढ़ा सकेगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष जैव-विविधता के मार्फत बचाया जा सकता है पर्यावरण

विजय

सुदर्शन सोलंकी अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप और कृत्रिम जलवायु परिवर्तन–जैव–विविधता के संकट को बढ़ाने में इंसान का सीधा हस्तक्षेप सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वन्यजीवों के अंगों की तस्करी, खाल, सींग और हड्डियों के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार इंसानी लालच का सबसे क्रूर चेहरा है। इसके अलावा, औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन (कोयला और तेल) के अंधाधुंध उपयोग। प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं है जिसका हम अपनी इच्छा से अनियंत्रित दोहन करते रहें, बल्कि यह वह जीवन–आधार है जिसके बिना हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। यदि हमने समय रहते अपने जंगलों, नदियों, सूक्ष्मजीवों और वन्यजीवों को नहीं बचाया, तो मानव सभ्यता का अंत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से हो जाएगा।जैव–विविधता पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीवों, पेड़–पौधों, पशु–पक्षियों, सूक्ष्म जीवों और उनके बीच के जटिल प्राकृतिक संतुलन का नाम है। हमारा मानव जीवन पूरी तरह से इसी ताने–बाने पर टिका हुआ है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जैव–विविधता हमारे अस्तित्व के लिए कई स्तरों पर अपरिहार्य है–दुनिया की लगभग आधी आधुनिक दवाइयां और एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक स्रोतों, वनस्पतियों और जड़ी–बूटियों से विकसित की गई हैं। प्रयोगशालाओं में बनने वाले रसायनों का आधार भी अक्सर प्रकृति ही होती है।कृषि, मत्स्य–पालन, पर्यटन और वनीकरण पर आधारित उद्योग दुनिया भर के करोड़ों लोगों को आजीविका और रोजगार प्रदान करते हैं। जैव–विविधता के क्षरण का सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के पतन के रूप में सामने आएगा। घने जंगल श्कार्बन सिंकश का कार्य करते हैं। ये वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने और श्ग्लोबल वार्मिंगश से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।विनाश की कगार पर दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न पर्यावरण संगठनों की हालिया रिपोर्टें जो आंकड़े पेश कर रही हैं, वे अत्यधिक चिंताजनक हैं। आज पूरी दुनिया जैव–विविधता के अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। डोडो पक्षी और तस्मानियन टाइगर जैसे जीव तो पहले ही धरती से गायब हो चुके हैं। भारत की बात करें, तो यहां की शान कहे जाने वाले जीव, जैसे – गोडावण, गिद्ध, लाल पांडा और हिम तेंदुआ आज गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।जैव–विविधता के इस तेजी से होते विनाश के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसान की अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, आधुनिक जीवनशैली और प्रकृति के चक्र में सीधा हस्तक्षेप है। इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं– तीव्र वनोन्मूलन–वैश्विक स्तर पर हो रही अंधाधुंध कटाई के कारण हर साल दुनियाभर में करीब 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। इससे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है और वे इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। जब किसी जीव का प्राकृतिक घर ही छीन लिया जाएगा, तो उसका अस्तित्व संकट में आना निश्चित है। प्रदूषण और प्लास्टिक का अभिशाप–हमारी नदियां और समुद्र औद्योगिक कचरे के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो चुके हैं। रासायनिक अपशिष्टों और सिंगल–यूज प्लास्टिक ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह तबाह कर दिया है। समुद्री जीव अनजाने में इस प्लास्टिक को निगल रहे हैं, जिससे पूरी खाद्य–श्रृंखला दूषित और प्रभावित हो रही है। अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप और कृत्रिम जलवायु परिवर्तन–जैव–विविधता के संकट को बढ़ाने में इंसान का सीधा हस्तक्षेप सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वन्यजीवों के अंगों की तस्करी, खाल, सींग और हड्डियों के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार इंसानी लालच का सबसे क्रूर चेहरा है। इसके अलावा, औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन (कोयला और तेल) के अंधाधुंध उपयोग, अनियंत्रित उत्सर्जन और कांक्रीट के विस्तार के कारण मानव–जनित जलवायु परिवर्तन हुआ है। वैश्विक तापमान में यह वृद्धि पूरी तरह इंसानी गतिविधियों की देन है। इसके कारण मौसम का चक्र इतनी तेजी से बदला है कि मूक जीव–जंतुओं और वनस्पतियों को संभलने या खुद को नए माहौल में ढालने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जिससे वे सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।श्मेगाडायवर्सिटीश और बड़ी चुनौतियां–भारत दुनिया के उन भाग्यशाली 17 श्मेगा डायवर्सिटीश देशों में शामिल है, जहां जैव–विविधता का अनमोल खजाना मौजूद है। हमारे पास श्पश्चिमी घाटश और पूर्वोत्तर भारत जैसे वैश्विक जैव–विविधता के हॉटस्पॉट हैं। अरावली पर्वतमाला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और थार मरुस्थल जैसे विशिष्ट इकोसिस्टम हैं, जो दुर्लभ जीवों को आश्रय देते हैं, लेकिन इस संपदा पर खतरा भी उतना ही बड़ा है। यदि यह विविधता नष्ट होती है, तो भारत में खाद्य–सुरक्षा, जल–संसाधन और मानव स्वास्थ्य पर ऐसा संकट खड़ा होगा जिससे निपटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। परागणकों (मधुमक्खियां और तितलियां) के खत्म होने से फसलों का उत्पादन गिर जाएगा, जिससे कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संरक्षण के प्रयास–भारत सरकार ने समय–समय पर प्रकृति को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और नीतियां बनाई हैं – श्बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002श के जरिए जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। श्प्रोजेक्ट टाइगरश और श्प्रोजेक्ट एलीफेंटश जैसी योजनाओं ने बाघों और हाथियों की आबादी को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्नमामि गंगेश और श्ग्रीन इंडिया मिशनश जैसी वृहद परियोजनाएं नदियों को पुनर्जीवित करने और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही हैं। हमें निम्नलिखित स्तरों पर तुरंत कार्य करना होगा– स्थानीय स्तर पर बदलाव– हमें अपनी जीवनशैली से प्लास्टिक को पूरी तरह बहिष्कृत करना होगा। कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और जल–संरक्षण को अपनी आदत बनाना होगा। सामुदायिक भागीदारी– ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को वनों और वन्यजीवों के संरक्षण से जोड़ना होगा। जब तक स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण बचाने का आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दिखेगा।

पद्म विभूषण, धर्मेंद्र और कानून–सम्मान के मंच पर परंपरा बनाम वैधता का प्रश्न

सुरेश

जीवन और योगदान निर्विवाद रूप से असाधारण रहा है। हिंदी सिनेमा में उनका छह दशकों का सफर एक युग की तरह देखा जाता है। शोले, मेरा गांव मेरा देश, चरस जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अमर चेहरा बनाया। 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में उनके निधन के साथ यह युग समाप्त हुआ। सरकार ने उनके निधन के बाद उन्हें मरणोपरांत यह उच्च सम्मान देना फिल्म जगत के सम्मान के रूप में देखा जा सकता है।25 मई 2026 को पद्म पुरस्कार के समारोह में जब धर्मेंद्र के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण की घोषणा हुई, तो स्वाभाविक रूप से वह क्षण भावनाओं से भरा था। मंच पर सम्मान ग्रहण करने पहुंचीं हेमा मालिनी को श्धर्मेंद्र की पत्नीश कहकर संबोधित किया गया। यह क्षण स्वाभाविक रूप से हृदयस्पर्शी था, लेकिन साथ ही उसने एक गंभीर प्रश्न भी खड़ा कियाकृ क्या सार्वजनिक और संवैधानिक मंचों पर सामाजिक स्वीकृति, कानूनी वैधता से ऊपर रखी जा सकती है? या फिर हम अनजाने में उन परंपराओं की ओर लौट रहे हैं जिन्हें आधुनिक भारत ने दशकों पहले पीछे छोड़ दिया था। यह प्रश्न केवल औपचारिक संबोधन का नहीं, बल्कि कानून और सामाजिक व्यवहार के बीच के उस अंतर का है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।धर्मेंद्र का जीवन और योगदान निर्विवाद रूप से असाधारण रहा है। हिंदी सिनेमा में उनका छह दशकों का सफर एक युग की तरह देखा जाता है। शोले, मेरा गांव मेरा देश, चरस जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अमर चेहरा बनाया। 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में उनके निधन के साथ यह युग समाप्त हुआ। सरकार ने उनके निधन के बाद उन्हें मरणोपरांत यह उच्च सम्मान देना फिल्म जगत के सम्मान के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सम्मान देने की प्रक्रिया में एक कानूनी–नैतिक प्रश्न अनिवार्य रूप से उभरता है। हिंदू विवाह अधिनियम (1955) ने हिंदू समाज में बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर एक विवाह को मान्य किया। पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक दूसरी शादी करना द्विविवाह का अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। हालांकि ऐसी अमान्य शादी से जन्मे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार पिता की संपत्ति में पूरा उत्तराधिकार प्राप्त है। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बीच तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में 1980 में हेमा मालिनी के साथ हुआ उनका विवाह, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, विधिक दृष्टि से वैध नहीं माना जा सकता। कानूनी दृष्टि से यह विवाह विवादित माना जाता रहा है। कानून स्पष्ट हैकृपहली शादी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है।मीडिया में यह भी चर्चा रही कि धर्मेंद्र और हेमा ने कथित रूप से इस्लाम अपनाकर निकाह किया था, ताकि हिंदू कानून की बाधा से बचा जा सके। हालांकि धर्मेंद्र ने सार्वजनिक रूप से इसे हमेशा नकारा। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याक्षी के रूप में दाखिल हलफनामे में उन्होंने पत्नी के रूप में केवल प्रकाश कौर का नाम लिखा और हेमा मालिनी का कोई उल्लेख नहीं किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरी शादी छिपाई। यह विवाद अदालत तक पहुंचा और लंबे समय तक चर्चा में रहा।यहीं से यह प्रश्न और जटिल हो जाता हैकृक्या किसी अमान्य विवाह को सार्वजनिक मंच पर वैध सामाजिक पहचान दी जा सकती है? और यदि दी जाती है, तो क्या यह कानून की भावना के विपरीत नहीं है? एक ओर संसद द्वारा पारित हिंदू विवाह अधिनियम है, जिसने बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कियाय दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन का मंच है, जहां उसी कानून के विपरीत संबोधन किया जाता है। ऐसे मामलों में यह प्रश्न उठता है कि क्या परिवार के सभी पक्षों को प्रक्रिया में शामिल किया गया था? यद्यपि यह निजी क्षेत्र का विषय है, लेकिन जब मामला राष्ट्रपति भवन के औपचारिक मंच तक पहुंचता है, तो यह केवल निजी नहीं रह जाता। इतिहास बताता है कि ऐसे मामलों में राज्य ने कई बार विधिक वैधता को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर पूर्व इन्दौर रियासत के उत्तराधिकार विवाद में अमेरिकी पत्नी से जन्मे बेटे रिचर्ड होल्कर (शिवाजीराव होल्कर) को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन द्वारा आपत्ति जताई गई थीकृयह दिखाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने समय–समय पर संस्थागत मर्यादाओं की रक्षा की है। इसी संदर्भ में यह प्रश्न और तीखा हो जाता है कि जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला राष्ट्रपति आसीन हैं, तब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की इस प्रकार की अनदेखी क्या एक विरोधाभास नहीं है? यह मुद्दा उस व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान को उजागर करता है, जहां हम कानून को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में परंपरागत मान्यताओं से संचालित होते रहते हैं। यहां हेमा मालिनी, और सनी देओल के राजनीतिक जीवन का संदर्भ भी दिलचस्प है। जहां पिता, पुत्र का राजनीतिक सफर अपेक्षाकृत सीमित रहा, वहीं हेमा मालिनी का सार्वजनिक जीवन अधिक लंबा और स्थिर रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सामाजिक स्वीकृति और राजनीतिक पहचान, कानूनी जटिलताओं के बावजूद, अपने रास्ते बना लेती है। चुनाव कवरेज लेकिन यही वह बिंदु है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि राज्य के औपचारिक मंचों पर भी कानून और सामाजिक सुविधा के बीच अंतर धुंधला होने लगे, तो यह एक खतरनाक मिसाल बन सकता है।इसी

संदर्भ में यह प्रश्न और तीखा हो जाता है कि जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला राष्ट्रपति आसीन हैं, तब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की इस प्रकार की अनदेखी क्या एक विरोधाभास नहीं है? यह मुद्दा उस व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान को उजागर करता है, जहां हम कानून को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में परंपरागत मान्यताओं से संचालित होते रहते हैं। यहां हेमा मालिनी, और सनी देओल के राजनीतिक जीवन का संदर्भ भी दिलचस्प है। जहां पिता, पुत्र का राजनीतिक सफर अपेक्षाकृत सीमित रहा, वहीं हेमा मालिनी का सार्वजनिक जीवन अधिक लंबा और स्थिर रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सामाजिक स्वीकृति और राजनीतिक पहचान, कानूनी जटिलताओं के बावजूद, अपने रास्ते बना लेती है। चुनाव कवरेज लेकिन यही वह बिंदु है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि राज्य के औपचारिक मंचों पर भी कानून और सामाजिक सुविधा के बीच अंतर धुंधला होने लगे, तो यह एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। यह विरोधाभास उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है जो बहुपत्नी परंपरा और आधुनिक भारत के संवैधानिक मूल्यों के बीच चला। हिन्दू स्मृतियों में पुरुषों को अनेक पत्नियां रखने की अनुमति थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में डॉ. भीमराव आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू स्त्रियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए हिंदू कोड बिल लाये। इसका जबरदस्त विरोध हुआकृरूढ़िवादी कांग्रेस नेता, दक्षिणपंथी संगठन, भारतीय जनसंघ और हिन्दुमहासभा, साधु संतकृ सभी इसके खिलाफ खड़े हो गए। यहां तक कि राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था।

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

ललित

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति–विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण–ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है। पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी–बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई–नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।' आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक–दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है। आवश्यकता इस चेतना को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदलने की है। समाधान क्या है? सबसे पहले विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, पूरक मानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बनाना, वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप देना और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं से यह कार्य संभव नहीं होगा, इसके लिए समाज, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिकों की साझी भागीदारी चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को राजनीतिक एजेंडा बनाना होगा। जिस प्रकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दे बनते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हरित विकास और जलवायु सुरक्षा भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनें। मतदाता अपने प्रतिनिधियों से पर्यावरण संबंधी दृष्टि और प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न पूछें। जब जनता पर्यावरण को प्राथमिकता देगी, तब राजनीति भी उसकी ओर मुड़ेगी। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय चेतना को व्यवहारिक रूप से शामिल करना होगा।

फांसी लगाकर युवती ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के महनपुर गांव में शनिवार को एक 18 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।इस मामले में जानकारी लेने पर थानाध्यक्ष बक्शा लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया महनपुर गांव निवासी

रुशी बिन्द (18) ने शनिवार सुबह घर के पीछे स्थित नीम के पेड़ से भैंस बांधने वाली रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह करीब साढ़े नौ बजे परिजनों की नजर उस पर पड़ी तो उसे तत्काल फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौपेड़वां ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बक्शा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच–पड़ताल की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतका के पिता बरखुराम बिन्द ने बताया कि उनकी पुत्री घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी। आत्महत्या के कारणों के संबंध में वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थाना कुमारगंज क्षेत्र में बनी एक और अस्थाई रूप से पुलिस चौकी

अयोध्या।जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर कई थाना क्षेत्र में अस्थाई रूप से पुलिस चौकी बनाए जाने का निर्देश जारी कर रहे हैं।किसी कड़ी में उन्होंने थाना कुमारगंज अन्तर्गत अस्थाई नवीन चौकी बीसा का पुरवा बनाये जाने का आदेश दिया।बताते चले चौकी बीसा का पुरवा क्षेत्र मे आने वाले गांव जगन्नाथपुर, बीसा का पुरवा, उपाध्याय का पुरवा, बृजवासी का पुरवा, मदरहा, पासिन का पुरवा, बीराभारी, बहादुरगंज, उधरन, बहबरमऊ, गोपालपुर, भटपुरा, इटौंजा शामिल रहेंगे।

अमृत सरोवरों पर विश्व पर्यावरण दिवस और योग दिवस को लेकर व्यापक जनभागीदारी के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यापक जनभागीदारी के साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर केवल जल संरक्षण के केंद्र नहीं हैं, बल्कि इन्हें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सहभागिता और जनजागरूकता के प्रभावी मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन स्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण समाज को पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक किया जाए।निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमृत सरोवरों के आसपास वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया है।इसके साथ ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमृत सरोवर स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, स्कूली छात्र–छात्राओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना सख्त

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद में विद्युत आपूर्ति, शिकायत निस्तारण तथा विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिजली आमजन से सीधे जुड़ी अत्यंत आवश्यक सेवा है, इसलिए इसकी निर्बाध आपूर्ति और समयबद्ध शिकायत निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी शिकायत का तत्काल संज्ञान लेकर उसका शीघ्र समाधान किया जाए।उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के साथ–साथ पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल जनपद है, इसलिए यहां विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व हानि रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।बठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि कई स्थानों पर जूनियर इंजीनियर (जेई) फोन रिसीव नहीं करते, जिससे समस्याओं के समाधान में देरी होती है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी जेई को निर्देश दिए ।

हरदोई के संडीला में ड्रैगन फ्रूट की खेती बनी कृषि नवाचार का सफल मॉडल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश का हरदोई जनपद अब परंपरागत खेती की सीमाओं को लांघकर बागवानी के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। संडीला विकास खंड में ड्रैगन फ्रूट (कमलम) की सफल खेती ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए पूरे क्षेत्र को कृषि नवाचार का मॉडल बना दिया है। कभी ऊसर और कम उपजाऊ मानी जाने वाली भूमि आज वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से उच्च मूल्य वाली फसल उत्पादन का केंद्र बन चुकी है।ड्रैगन फ्रूट की खेती ने न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन की अवधारणा को भी साकार किया है। इस फसल के लिए संडीला क्षेत्र की जलवायु विशेष रूप से अनुकूल पाई गई है, जहां गर्म और शुष्क मौसम पौधों के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। कम सिंचाई आवश्यकता के कारण यह फसल भूजल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में उत्पादित फल स्थानीय मंडियों के साथ–साथ लखनऊ सहित बड़े शहरी बाजारों में भी अच्छी कीमत पर बिक रहा है, जिससे किसानों को स्थायी और उच्च आय प्राप्त हो रही है।ड्रैगन फ्रूट को पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सुपरफूड माना जाता है, जिसके चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। एक बार पौधरोपण के बाद यह फसल कई वर्षों तक उत्पादन देती है और लगभग 20 से 25 वर्षों तक आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है।

समय से पहले विधानसभा चुनाव के आसार, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी करें - राकेश मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को जिला कार्यालय सदर चुंगी में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अभी से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाकर समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य कर रही है और इसी आधार पर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला महासचिव आरिफ हबीब ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कराई तथा कार्यकर्ताओं से सुझाव प्राप्त किए। बैठक को जिला उपाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया और संगठन विस्तार तथा जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान पार्टी के नवमनोनीत पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय सचिव चंद्रशेखर यादव, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के अजय रंजन यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र चौरसिया तथा कार्यवाहक नगर अध्यक्ष अशफाक मंसूरी को माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में कमलेश यादव, कमाल आजमी, संदीप यदुवंशी, अनुज दुबे, सुशील श्रीवास्तव, उमेश यादव, अफरोज हुसैनी, विवेक यादव, विकास यादव, मुकेश यादव, अजीज फरीदी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

गांवों में बीएसएनएल को मोबाइल टॉवर लगाने के लिए मुफ्त मिलेगी जमीन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 112 नए चिह्नित स्थानों पर 4जी मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए बीएसएनएल को ग्राम सभा की जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला किया

है। इसके लिए प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने संबंधित डीएम को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, बीएसएनएल को मोबाइल टॉवर निर्माण के लिए प्रत्येक स्थान पर 200 वर्गमीटर (10 मीटर – 20 मीटर) भूमि दी जाएगी। इनमें 95 स्थान पूर्वी यूपी और 17 स्थान पश्चिमी यूपी में चिह्नित किए गए हैं। शासनादेश में साफ किया है कि केवल अनारक्षित श्रेणी की भूमि, जैसे नवीन परती, ऊसर और बंजर भूमि का ही हस्तांतरण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि, मई 2026 में कर राजस्व 20,491 करोड़ रुपये तक पहुंचा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत दिशा में अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के मई माह में प्रदेश सरकार को मुख्य कर एवं करेतर राजस्व मदों से कुल 20,491 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में प्राप्त 18,120 करोड़ रुपये की तुलना में 2,371 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार और राजस्व संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।यह जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने बताया कि राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ा योगदान जीएसटी का रहा, जिसमें मई 2026 में 7,551 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में यह 5,209 करोड़ रुपये था। इस प्रकार जीएसटी संग्रह में 2,342 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से 2,994 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग से 1,228 करोड़ रुपये, वैट से 3,010 करोड़ रुपये तथा आबकारी विभाग से 5,388 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभिन्न विभागों में यह प्रदर्शन राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।वित्तीय वर्ष 2026–27 में मई माह तक कर राजस्व के अंतर्गत 55,641.02 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 41,621.54 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो कुल लक्ष्य का 74.8 प्रतिशत है। राज्य कर मद में 34,054.25 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 21,452.89 करोड़ रुपये की प्राप्ति दर्ज की गई है, जो 63 प्रतिशत उपलब्धि है। वहीं जीएसटी मद में 27,676.45 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 17,334.35 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है, जो 62.6 प्रतिशत लक्ष्य के बराबर है।प्रमुख विभागीय प्रदर्शन में आबकारी विभाग ने 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है, जबकि परिवहन विभाग ने 100.6 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। ऊर्जा विभाग ने 136.7 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने 84.4 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है।सरकार के अनुसार प्रदेश में राजस्व वृद्धि के साथ–साथ जनहित में कर दरों को संतुलित बनाए रखा गया है। वर्तमान में पेट्रोल पर 19.36 प्रतिशत या 14.85 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 17.08 प्रतिशत या 10.41 रुपये प्रति लीटर कर लागू है। राज्य में पेट्रोल की कीमत 101.86 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 95.36 रुपये प्रति लीटर है।

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन सात से, 15 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक कर सकेंगे आवेदन

लखनऊ, (संवाददाता)। बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार–2025 के लिए चयन प्रक्रिया व समयसारिणी जारी कर दी है। पात्र शिक्षक 07 से 30 जून तक प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षक आवेदन के साथ अपना पोर्टफोलियो भी देंगे। पुरस्कार के लिए केवल नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका ही पात्र होंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल की नियमित सेवा और सेवानिवृत्ति में कम से कम पांच साल की अवधि शेष होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, सेवानिवृत्त शिक्षक व पूर्व में राज्य

या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक पात्र नहीं होंगे। 1 से 20 जुलाई तक जिला चयन समितियां प्राप्त आवेदनों का परीक्षण, अभिलेख सत्यापन व मूल्यांकन करेंगी। चयनित आवेदनों का राज्य स्तर पर 1 से 14 अगस्त तक पुनर्मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण व साक्षात्कार होगा। शिक्षकों का मूल्यांकन 100 अंकों पर होगा। इसमें विद्यालय में नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट में कमी, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति, नवाचार आधारित शिक्षण, डिजिटल तकनीक के प्रयोग, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों व विद्यालय विकास में योगदान जैसे मानक हैं।

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर परिश्रम संस्था ने 54 दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल और 54 छात्राओं को साइकिल वितरित की

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था परिश्रम द्वारा शुक्रवार को जनसेवा एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह और सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 54 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल तथा 54 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। साथ ही 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 11 किलो के मावा के केक का काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद के. पी. सिंह ने कहा कि परिश्रम संस्था का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को जनसेवा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना सराहनीय पहल है, जिससे समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बल मिलता है। संस्था के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं संस्था के सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे ने कहा कि समाज के सहयोग से ही ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम सफल होते हैं और संस्था भविष्य में भी सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखेगी।

साइकिल प्राप्त कर छात्राओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अब विद्यालय आने–जाने में सुविधा होगी। वहीं ट्राइसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति गीतों के बीच लाभार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, अजय सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, हरेंद्र प्रसाद सिंह, सुषमा पटेल, ओमप्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

गोमती नदी में नहाते समय छह युवक डूबे, दो की मौत, चार को बचाया गया

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी के सद्भावना पुल के पास विसर्जन घाट पर शुक्रवार शाम स्नान के दौरान छह युवक नदी में डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों की तत्परता से चार युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो युवक लापता हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने देर रात दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी दिलीप पटेल (24) पुत्र दशरथ पटेल तथा नितिन विश्वकर्मा (20) पुत्र मुटूर विश्वकर्मा निवासी मिर्जामुराद, वाराणसी के रूप में हुई है। नितिन अपने मित्र के यहां जगदीशपुर आया हुआ था। शुक्रवार शाम सभी छह युवक गोमती नदी में स्नान करने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान के दौरान सभी युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय देते हुए चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दिलीप और नितिन पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से तलाश अभियान शुरू कराया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात दोनों युवकों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। घटना में बचाए गए युवकों में प्रहलाद पटेल (24) पुत्र बृजभूषण पटेल निवासी जगदीशपुर, जौनपुर, दीपक पटेल (24) पुत्र दशरथ पटेल निवासी जगदीशपुर, जौनपुर, सचिन कुमार पटेल (22) पुत्र राजकुमार पटेल निवासी राजातालाब, मिर्जामुराद, वाराणसी तथा अजय शंकर पटेल (23) पुत्र रमाशंकर पटेल निवासी राजातालाब, मिर्जामुराद, वाराणसी शामिल हैं। इस मामले में जानकारी लेने पर अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

कोचिंग जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत बक्शा में अज्ञात वाहन ने कुचला, पुलिस जांच में जुटी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बक्शा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कोचिंग जा रही एक हाईस्कूल छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान महराजगंज थाना क्षेत्र के उमरीकला गांव निवासी रामप्रसाद गौतम की पुत्री रौनक गौतम (17) के रूप में हुई है। रौनक अपने ननिहाल दक्षिणपट्टी गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे धनियांमऊ स्थित कोचिंग संस्थान जाने के लिए निकली थी कि नेशनल हाईवे–731 पर श्रीनारायण सिन्हा इंटर कॉलेज, सरायहरखू के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी,

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए तथा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौपेड़वां ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन शव को घर ले गए।। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

'मानव सेवा में रेडक्रॉस और लोकभारती का बेमिसाल संगम'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी कार्यालय में लोकभारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव एवं समाजसेवी डॉ. विजय जौहरी से भेंट कर उनके जनहित एवं मानवीय सेवा कार्यों की सराहना करते हुए लोकभारती के पदाधिकारियों ने कहा कि जनपद स्तर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा मानव सेवा, जनजागरूकता एवं राहत कार्यों में निभाई जा रही सक्रिय भूमिका ही उसके प्रति समाज के बढ़ते विश्वास का आधार है। रेडक्रॉस के साथ सहयोग की लोकभारती की पहल इस बात का प्रमाण है कि संस्था जनहित एवं मानवता की सेवा में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। दोनों संगठनों ने भविष्य में भी जनकल्याण एवं राष्ट्रहित के कार्यों में संयुक्त रूप से सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर डॉ जौहरी ने कहा की ष्रेड क्रॉस सोसाइटी की जनपद स्तर पर सक्रिय मानवीय सेवाएँ ही उसके प्रति समाज के विश्वास का आधार हैं। लोकभारती का सहयोग एवं सम्मान इस बात का प्रमाण है कि संस्था मानव सेवा के प्रति अपने दायित्व का प्रभावी निर्वहन कर रही है। "लोकभारती के पदाधिकारियों के ये शब्द मेरे लिए प्रेरणास्रोत हैं। इससे मानव सेवा के प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैं जनपद में समर्पित भाव से मानव सेवा के कार्यों का निरंतर निर्वहन करता रहूँगा।" उन्होंने लोकभारती के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज में किए जा रहे सेवा कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन और प्रोत्साहन समाजसेवा की भावना को सशक्त बनाता है। उन्होंने रेड क्रॉस का प्रतीक चिह्न एवं सम्मान–पट्टिका प्रदान कर अतिथियों का अभिनंदन किया तथा मैडल पहनाकर ओढ़ने के वस्त्र एवं गौशाला प्रबंधन के तिरपाल भेंट किया। लोकभारती के प्रतिनिधियों ने बताया कि संगठन किसान कल्याण, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, राष्ट्रचेतना एवं मानव सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज, संगठन से राष्ट्रहित एवं जनकल्याण के कार्यों में अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करने की अपेक्षा रखता है और लोकभारती इस दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है।लोकभारती के पदाधिकारियों ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित स्वास्थ्य, राहत एवं जनसेवा कार्यक्रमों की सराहना करते हुए भविष्य में भी जनहित के कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गोरक्षा परम्परा के संत और अध्यक्ष, गोरक्ष पीठ स्थान के महंत योगी हनुमान नाथ कामधेनु अवतरण अभियान न्यूरानपुर, पीलीभीत, सह संगठन मंत्री लोकभारती गोपाल जी, अध्यक्ष, ब्रजप्रांत लोकभारती डॉ विजय पाठक (सर्जन), सह संपर्क प्रमुख, लोकभारती संजय उपाध्याय, भाजपा के वरिष्ठ नेता रजनीश दीक्षित लखीमो , ऊँ दिव्यांगजन कल्याण समिति के बालकृष्ण पाण्डेय, बृजेश गुप्ता मुरारी लाल राठौर आदि कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनपद में 5 लाख से अधिक पौधों का हुआ रोपण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद अयोध्या में ष्एक पेड़ मां के नामष् अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने माझा जमथरा मे पौधरोपण किया।इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि ष्एक पेड़ मां के नामष् अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ–साथ मातृत्व के सम्मान का भी प्रतीक है।जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजन के सहयोग से 5 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ–साथ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया

जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम के तहत जनपद में मियांवाकी पद्धति के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है। वृक्षारोपण का कार्य आगे भी जारी रहेगा।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित अयोध्या के निर्माण के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करने तथा पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर विधायक रुदौली रामचंद्र यादव,विधायक मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान,विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी प्रखर गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह,संयुक्त निदेशक कृषि एके मिश्रा, उपनिदेशक कृषि पीके कन्नौजिया,जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी अशोक,उप जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

थाना साइबर क्राइम टीम ने पीडित को लौटाया 374948 रुपये

अयोध्या। थाना साइबर क्राइम टीम ने पीड़ित को 374948 वापस कराया।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम मोहम्मद अरशद ने बताया कि थाना साइबर क्राइम जनपद–अयोध्या के एनसीआरपी पोर्टल पर एक शिकायत आई थी।जिसमे आवेदक के खाते से 336948 रुपये से कट गये थे।बताया कि आवेदक के यूपीआई के माध्याम से 38000 रुपये कट जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त शिकायतो मे 374948/– रुपये थाना साइबर क्राइम द्वारा वापस कराया गया।

तथाकथित भाजपा नेता सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ भाजपा के ही नेता राघवेंद्र प्रताप तिवारी ने लगाया आरोप

अयोध्या। शनिवार को तथाकथित भाजपा नेता सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ एक बार फिर भाजपा के ही नेता राघवेंद्र प्रताप तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यह आप शहर की सिविल लाइन स्थित होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अपने को भाजपा नेता बताने वाले सच्चिदानंद पांडे कई लोगों से रुपया लेकर फ्रॉड किया और वापस नहीं किया।इनके खिलाफ तीन मुकदमे भी जानकारी के मुताबिक दर्ज हैं।बताया कि 27 जनवरी 2026 को अतरौलिया में घ्500000 हड़पने का केस दर्ज हुआ जिसमें इन्होंने 3 लाख वापस किया 2 लाख मांगने पर पीड़ित से मारपीट की।दूसरा मुकदमा भाजपा आईटी सेल की प्रभारी प्रवेश मिश्रा ने फोन पर गाली गलौज का हैदरगंज थाने में दर्ज कराया और तीसरा मुकदमा 3 जून 2026 को परमहंस ने घ्200000 हड़पने का कोतवाली अयोध्या में दर्ज हुआ है।बताया कि सच्चिदानंद पांडे अपने आप को मृत्यु दिखाने के लिए हरदोई में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया,उसमें अपना पुतला रखवाया बाद मे हुई जांच में सारे मामले सामने आए।बताया कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में वे जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी को एक ज्ञापन देंगे

बिना आईडी के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण नहीं कर सकते खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मी

अयोध्या। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अब बिना आईडी के किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर जाकर निरीक्षण नहीं कर सकते हैं।अगर बिना आईडी लगाए खाद्य सुरक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी निरीक्षक व कर्मी किसी भी प्रतिष्ठा का निरीक्षण करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठा के स्वामी इसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों को दें जिससे कि उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जा सके।इस बात की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि यह कदम किस लिए उठाए जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा मुख्यालय में कई जिलों से शिकायतें जा रही थी कि उक्त जिलों में फर्जी खाद्य निरीक्षक तथा अधिकारी बनकर मिठाईयां तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर

वसूली कर रहे हैं इसी पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। बताया कि इसी आदेश के तहत शनिवार को उन्होंने फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सभी अधिकृत अधिकारियों को विशेष पहचान पत्र जारी किए।बताया कि 1 मई 2026 से लागू नए नियम के तहत अब बिना नई विभागीय आईडी के कोई भी अधिकारी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में जांच नहीं कर सकेगा।सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने व्यापारियों से अपील की है कि बिना आईडी वाले व्यक्ति को जांच न करने दें और तुरंत विभाग को सूचना दें।

अयोध्या के अब पांच चौराहों पर शुरू हुआ आईटीएमएस सिस्टम

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। नगर निगम ने श्री रामनगरी की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।अब शहर के पांच प्रमुख चौराहों पर आईटीएमएस का संचालन शुरू कर दिया गया है।इससे यातायात नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा और नागरिकों को रेड एवं ग्रीन सिग्नल के अनुसार सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।शनिवार को आईटीएमएस प्रणाली का शुभारंभ महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने जलकल परिसर स्थित आईटीएमएस कार्यालय से किया। इस मौके पर उपसभापति संतोष सिंह मौजूद थे। नगर निगम ने रकाबगंज चौराहे पर पहले से संचालित आईटीएमएस प्रणाली के अतिरिक्त शांति चौक (नाका), गुदड़ी बाजार चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा तथा पुलिस लाइन स्थित पुष्पराज चौराहा पर भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।इस अवसर पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर धर्मपथ पर हनुमान गुफा, सिविल लाइन चौराहा, देवकाली बाईपास एवं मनूचा चौराहा सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी आईटीएमएस प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इससे यातायात संचालन और अधिक सुचारु होगा तथा आमजन को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा 20 चौराहों पर सीबी इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी स्थापित किए गए हैं।इन स्थानों पर जागरूकता के लिए विशेष स्टीकर लगाए गए हैं।किसी भी आपातकालीन स्थिति, सड़क दुर्घटना, चोरी अथवा अन्य संकट की स्थिति में नागरिक एसओएस बटन दबाकर तत्काल सूचना नगर निगम और पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इससे पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि शहर के 15 अन्य स्थानों पर भी आईटीएमएस सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है, इनमें निषाद राज चौराहा (टेढ़ी बाजार),श्रीराम हॉस्पिटल तिराहा, लता चौक, हनुमान गुफा चौक, साकेत पेट्रोलियम, देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहा, अग्रसेन तिराहा, रायबरेली बाईपास, सहादतगंज बाईपास, नाका हनुमानगढ़ी, डीएम आवास चौराहा, गुरु गोविंद सिंह चौक एवं सिविल लाइन तिराहा प्रमुख हैं।

सांसद ने झाड़ू उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश, बटोरा कचरा,कहा– हर नागरिक की जिम्मेदारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गोरखपुर के सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने मंगलवार को श्रमदान एवं प्लॉग रन अभियान में हिस्सा लिया। नौका विहार क्षेत्र में महापौर और पार्षदों के साथ मिलकर उन्होंने प्लास्टिक कचरा एकत्र किया और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। गोरखपुर महानगर के नौका विहार क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सांसद रवि किशन के साथ महानगर जिलाध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव तथा नगर निगम के पार्षदों ने श्रमदान किया। सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन से लोगों में सकारात्मक सोच विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है । रवि किशन ने कहा कि समस्त गोरखपुर और नौका विहार को प्लास्टिक मुक्त एवं प्रदूषण मुक्त बनाना केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है। यदि हर नागरिक आसपास स्वच्छता का संकल्प ले तो शहर और देश दोनों सुंदर बन सकते हैं। अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

नजूल के भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए निर्माण पर चला बुलडोजर

अयोध्या।कोतवाली नगर क्षेत्र में नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हुए भवन, दुकान तथा अन्य निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है।बताते चले कि शुक्रवार को जहां चौक स्थित सब्जी मंडी बुलडोजर चला वही। शनिवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के पुष्पराज चौराहे के पास नजूल भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया।यह कार्यवाई जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने संयुक्त रूप से की गई। यहां पर कार्यवाही करते हुए नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि यह भूमि सरकारी नजूल संपत्ति है।बताया कि सरकारी जमीनों

पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया कि यहां पर खाली कराए जा रहे अतिक्रमण के बाद खाली भूमि का उपयोग विकास और जनहित के कार्यों में किया जाएगा।कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात रही। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करना होगी सर्वोच्च प्राथमिकता : एआरएम

अयोध्या।धर्णेन्द्र कुमार चौधरी ने एआरएम रोडवेज अयोध्या के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया।चित्रकूट जिले से स्थानांतरित होकर आये नवागत एआरएम रोडवेज श्री चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करने की पश्चात कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक आरामदायक सुविधा करना है।रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निगम लगातार प्रयासरत रहेगा।कहा कि रोडवेज यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान,समयबद्ध बस संचालन तथा स्वच्छ बस अड्डों की व्यवस्था उनकी प्राथमिकता रहेगी।जनपद में परिवहन सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा और बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके।एआरएम ने कर्मचारियों से भी यात्रियों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाने का आह्वान किया।इसके साथ–साथ सिविल लाइन स्थित रोडवेज बस स्टैंड से विभिन्न रूटों को जाने वाली बसों को समय से संचालित करना है।बताया कि यहाँ पर तैनात चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी एवं कार्यालय मे तैनात कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान,कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण तथा उनके सम्मान की रक्षा उनकी प्राथमिकताओं मे से एक है।

जमीनी विवाद में पट्टीदारों के बीच चले लाठी–डंडे, छह घायल

गोरखपुर, (संवाददाता)। उरुवा क्षेत्र के सुल्तानी गांव में बोरिंग कराने को लेकर हुए जमीनी विवाद ने बृहस्पतिवार सुबह हिंसक रूप ले लिया। पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट में जमकर लाठी–डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के छह लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, विवाद जमीन पर बोरिंग कराने को लेकर उत्पन्न हुआ था, जो देखते ही देखते कहासुनी और फिर मारपीट में बदल गया। घटना के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बीच–बचाव कर मामला शांत कराया। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा बाजार पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में एक पक्ष से अश्वनी, मीरा और पूजा व दूसरे पक्ष से शशिकांत, रामसूरत एवं मनभावती शामिल हैं।

स्कूटी चार्ज करते समय करंट लगने से छात्र की मौत

गोरखपुर, (संवाददाता)। रामगढ़ताल इलाके के यशोदरा कुंज मोहल्ले में बुधवार सुबह इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय छात्र प्रांजल यादव की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे किशोर को परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार को छात्र का शव गगहा में गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुवान गांव निवासी प्रमोद यादव परिवार के साथ यशोदरा कुंज स्थित अपने मकान में रहते हैं। बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उनका बेटा प्रांजल यादव चार्जिंग व्यवस्था के संपर्क में आ गया। करंट का झटका इतना तेज था कि वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि घटना के समय प्रांजल की मां मकान की पहली मंजिल पर थीं। चीख–पुकार और आसपास के लोगों के शोर मचाने पर वह नीचे पहुंचीं तो बेटे को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलने पर पिता भी तत्काल घर पहुंचे। परिजन आनन–फानन में प्रांजल को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, गमगीन माहौल में छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जूडो–कराटे में भी था अव्वल रू परिजन और ग्रामीणों के अनुसार, प्रांजल पढ़ाई में मेधावी छात्र था। वह जूडो–कराटे का अच्छा खिलाड़ी भी था और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका था। कम उम्र में उसकी प्रतिभा और अनुशासन की क्षेत्र में चर्चा रहती थी। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार ही नहीं, पूरे गांव और परिचितों को स्तब्ध कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि होनहार बेटे की असमय मौत से माता–पिता गहरे सदमे में हैं।

'शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करें–अनुनय झा'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शनिवार को जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सदर तहसील सभागार में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, सिंचाई, समाज कल्याण, नगर निकाय एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं, जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य की समस्याओं

का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्राप्त प्रकरणों का मौके पर जाकर सत्यापन करें तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने–अपने विभागों से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लिया तथा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि थाना अन्तर्गत गांव के लोगों से समन्वय बनाकर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी लें तथा आसामाजिक, आराजक एवं दंबग लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें और शान्ति व्यवस्था हलहाल में बनाये रखें। इस अवसर पर सीएमओ डा0 भावनाथ पाण्डे, उप जिलाधिकारी सदर मंयक कुण्डू, तहसीलदार सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, संबंधित ब्लाक के खंड विकास अधिकारी, सीडीपीओ, थानाध्यक्ष सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डीडीयू चार वर्ष का स्नातक अब तीन वर्ष में ही पूर्ण कर सकेंगे विद्यार्थी

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक के विद्यार्थियों को अधिक लचीली और छात्र केंद्रित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अहम बदलाव की तैयारी है। इसके तहत मेधावी विद्यार्थी चार वर्ष का पाठ्यक्रम अब तीन वर्ष में ही पूर्ण कर सकेंगे। इसके लिए डीडीयू प्रशासन ने समिति गठित कर दी है। यूजीसी की ओर से विनियम–2025 के तहत त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (ईडीपी) का प्रावधान किया गया है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता, रुचि व व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन अवधि में लचीलापन प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत मेधावी विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम और आवश्यक क्रेडिट समय से पहले पूरा कर कम अवधि में डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, वह विस्तारित अवधि में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके तहत पाठ्यक्रम, शिक्षण गुणवत्ता, क्रेडिट, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली नियमित कार्यक्रमों के समान ही रहेगी। केवल अध्ययन अवधि में बदलाव होगा। तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को विद्यार्थी पांच सेमेस्टर में या चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को छह या सात सेमेस्टर में पूरा कर सकेंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।